बच्चों के टीके

4037. श्री महेन्द्र सिंह लाठर : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 31 दिसम्बर, 1991 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित "ग्लोबल मूव फॉर चिल्ड्रन्स वैक्सीन्स" नामक समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास जेनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा चिल्ड्रन्स वैक्सीन इनिशिएटिव (सी०आई०वी) सेमिनार में लिये गये निर्णय की जानकारी है, यदि हां, तो वर्ष 1990 से भारत में चेचक तथा अन्य संक्रामक रोगों से बच्चों की रक्षा करने वाले टीकों का निर्माण करने तथा ऐसे टीकों के आयात और निर्यात करने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई भावी योजना तैयार की है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) जी हां, सरकार विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनीसेफ, यू०एन०डी०पी०, रॉकफेलर फाउन्डेशन और विश्व बैंक के चिल्ड्रन्स वैक्सीन इनिशिएटिव (सी०वी०आई०) सम्बन्धी कार्यक्रम के अन्तर्गत गतिविधियों से अवगत है ।

(ख) चिल्ड्रन्स वैक्सीन इनिशिएटिव (सी०वी०आई०) का उद्देश्य नये एवं बेहतर टीकों के इस्तेमाल द्वारा प्रमुख शैशवकालीन संक्रामक रोगों के लिये अधिक कारगर टीकों को बढ़ावा देना, विकसित करना और उपलब्ध कराना है । इन रोगों के लिये ये टीके बहुत थोड़ी खुराक में, यदि सम्भव हो, तो जन्म के समय बच्चे की पूर्ण सुरक्षा के लिये दिये जा सकते हैं । सी०वी०आई० द्वारा निम्नलिखित परियोजनाएं शुरू की गई हैं :—

(1) उष्मा स्थिर यू०पी०वी० का विकास करना जो विकासशील देशों की परिस्थितियों के अन्तर्गत प्रयोग के लिये अधिक उपयुक्त होगा ।

(2) गर्भवती महिलाओं के लिये सिंगल डोज टिटनेस टोक्साइड वैक्सीन जिसकी एक ही खुराक टिटनेस से बचाव करेगी ।

(3) बेहतर खसरा टीका जो 9 महीने की आयु से पहले लगाया जा सकता है ; और

(4) नये और बेहतर टीकों का सम्मिश्रण जिससे बच्चे को टीका केन्द्र तक बार-बार नहीं ले जाना पड़े ।

सरकार सी०वी०आई० के अन्तर्गत गतिविधियों से पूरी तरह अवगत रहती है, क्योंकि सचिव, बायोटेक्नोलॉजी विभाग को चिल्ड्रन्स वैक्सीन इनिशिएटिव प्रबन्ध सलाहकार समिति और प्राथमिकता स्थापन एवं क्रियाविधि आयोजन सम्बन्धी कार्य दल का अध्यक्ष चुना गया है ।

(ग) भारत सरकार ने अगले कुछ वर्षों में ई०पी०आई० और गैर ई०पी०आई० टीकों की आवश्यकताओं के संदर्भ में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की विस्तृत योजना तैयार की है, जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है । जब कभी ऐसे उत्पाद स्वीकृत और उपलब्ध हो जायेंगे तो भारत में प्रतिरक्षण कार्यक्रम में नये और बेहतर टीकों को चालू किया जायेगा । गैर-सरकारी और सरकारी, दोनों क्षेत्रों में सुदृढ़ अनुसंधान एवं विकास क्षमता विकसित की जा रही है ।

विवरण

सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम के लिए विभिन्न फर्मों की उत्पादन क्षमता और टीकों की मांग

(लाख खुराकों में)

एकक	प्रतिजनक					
	डी.पी.टी.	डी.टी.	टी.टी.	ओ.पी.बी.	बी.सी.जी.	खसरा
क. क्षमता						
सी.आर.आई., कसौली (भारत सरकार का एकक)	23.0	25.0	30.0	—	—	—
पी.आई.आई., कनूर (भारत सरकार का एकक)	16.5	11.0	11.0	—	—	—
बी.सी.जी., गुण्डी, मद्रास (भारत सरकार का एकक)	—	—	—	25.0	—	—
एच.बी.पी.सी.एल., बम्बई (महाराष्ट्र सरकार का एकक)	7.0	6.0	12.0	50.0	—	—
एस.बी.आई., पटवाडनगर (उ.प्र. सरकार का एकक)	—	—	2.0	—	—	—
एस.आई.आई., पुणे (निजी क्षेत्र)	114.0	40.0	150.0	—	—	70.0
बी.ई., हैदराबाद (निजी क्षेत्र)	24.0	—	24.0	—	—	—
रेड्डीकरा फार्मा (निजी क्षेत्र)	—	—	—	100.0	—	—
बिवकॉल (भारत सरकार का एकक)	—	—	—	100.0	—	—
कुल क्षमता	184.5	82.0	229.0	250.0	25.0	70.0
ख. सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम की वार्षिक मांग	120.0	55.0	115.0	175.0	45.0	45.0